राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ

एकलपीठ आपराधिक अपील संख्या 8014/2022

संजय सिंह कच्छवाहा पुत्र जीतेन्द्र सिंह कच्छवाहा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी बी-30 हरि दासजी-की-मगरी, मल्ला तलाली, उदयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री निशांत बोरा
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री अभिषेक पुरोहित, अतिरिक्त जी.ए.

माननीय *न्यायमूर्ति* पुष्पेंद्र सिंह भाटी

निर्णय

रिपोर्टेबल

12/12/2022

1. यह आपराधिक विविध याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निम्नलिखित प्रार्थना का दावा करके दायर की गई है:-

"इसलिए यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आवेदन को अनुमति दी जाए और:

(i) न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम मामले, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 को कृपया रद्द कर दिया जाए और सीसी टीवी फुटेज को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लेने के लिए आरोपी प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति प्रदान की जाए।

(ii) बचाव पक्ष को निशान प्रदर्शित करने और सीसी टीवी फुटेज वाली सीडी चलाने और जिरह में चश्मदीदों का सामना करने की अनुमति दी जाए।

(iii) आपराधिक विविध प्रकरण क्रमांक 168/2018 में विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण मामले) उदयपुर (एसआईसी) के समक्ष लंबित कार्यवाही को निरस्त कर निरस्त करने की कृपा करें।

(iv) "कोई अन्य उचित आदेश या निर्देश जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझा जाए, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जा सकता है।

2. मामले में रखे गए तथ्यों के सार तथ्यऔर रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है, कि शिकायतकर्ता-महेंद्र छापरवाल, उनके भाई-गजेंद्र छापरवाल, उनके चाचा-मुरली छापरवाल और राहुल तम्बोली मोटरसाइकिल और स्कूटी पर कन्हैया पेट्रोल पंप से अपने घर की ओर यात्रा कर रहे थे,तब तीन आरोपियों, सुनील लोट उर्फ बंटी, दीपक चंदेल उर्फ गुड्डू और रमेश चंदेल ने शिकायतकर्ता पक्ष पर गोलियां चला दीं। उसी के परिणामस्वरूप, गजेंद्र छापरवाल को अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया, जबकि राहुल तम्बोली को चोटें आईं।

3. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में दिनांक 22.07.2018 को पुलिस स्टेशन अंबामाता, उदयपुर में उपर्युक्त तीनों आरोपियों के खलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 302, 120-ख और शस्त्र अधिनियम1959 की धारा 3/25, के तहत अपराध के लिए एफ.आई.आर. दायर की गई। जांच करने पर, 14.10.2018 को एक आरोप-पत्र दायर किया गया, जिसमें चार और लोगों को भी शामिल किया गया, और सभी आरोपियों के खिलाफउपर्युक्त एफ.आई.आर. में वर्णित आरोपों के अलावाशस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 5/25 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (2015 में यथा संशोधित) की धारा 3 (2) और 5 (1) के तहत अपराध के लिए आरोप लगाए गए।

4. वर्तमान विवाद की उत्पत्ति सीसीटीवी फुटेज है, जो जांच के दौरान संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा एकलिंगनाथ गार्डन से प्राप्त की गई थी, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया था। आरोप-पत्र के साथ इसकी एक प्रति आरोपी व्यक्तियों को भी दी गई थी। न्यायालय को और आरोपी व्यक्तियों को उक्त सीसीटीवी फुटेज की प्रति एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सी.डी. के माध्यम से प्रदान की गई थी। हालाँकि, न्यायालय में प्रस्तुत की गई सीडी का विवरण टूट गया, अत: उसे देखा नहीं जा सका। इसके बाद, बचाव पक्ष ने सी.आर.पी.सी. की धारा 91 के तहत आवेदन द्वारा

विद्वान न्यायाधीश के समक्ष संबंधित गवाहों से संबंधित 21.07.2018 से 15.08.2018 की अवधि के लिए कॉल विवरण, स्थान और रोजनामचा रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश देने की मांग की। जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा ख़ारिज कर दिया गया। इसके बाद, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 और 65ख के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें संबंधित पुलिस प्राधकारियों द्वारा आरोप-पत्र के साथ दी गई प्रश्नगत घटना की सीडी की कॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की मांग की गई थी। हालाँकि, इसे विद्वान न्यायालय ने दिनांक 30.09.2022 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर आक्षेपित आदेश की आलोचना की कि यह ***अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल और अन्य (2020) 7 एससीसी 1*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप नहीं है। और इसलिए आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

इस न्यायालय का ध्यान उपरोक्त निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफ की ओर आकर्षित किया गया: -

"50. हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि धारा 65ख उस चरण के बारे में नहीं बताती है जिस पर ऐसा प्रमाणपत्र न्यायालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनवर पी.वी. (सुप्रा.),मामले मेंइस न्यायालय ने यह देखा कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर इस तरह के प्रमाणपत्र को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हम केवल यह जोड़ सकते हैं कि ऐसा उन मामलों में होता है जहां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर भरोसा करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां या तो दोषपूर्ण प्रमाणपत्र दिया गया है, या ऐसे मामलों में जहां ऐसे प्रमाणपत्र की मांग की गई है और संबंधित व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया है, मुकदमे पर विचार करने वाले न्यायाधीश को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी(4) में निर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों को बुलाना होगा और यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा दिया जाए। ट्रायल जज को ऐसा तब करना चाहिए जब उपरोक्त परिस्थितियों में आवश्यक प्रमाणपत्र के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में उसके सामने पेश किया जाता है। निःसंदेह, यह सिविल मामलों में विधि के अनुसार और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर न्याय की आवश्यकताओं के अनुसार विवेक के प्रयोग के

अधीन है। जब दांडिक विचारण की बात आती है, तो सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखना जरूरी है कि अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत मुकदमा शुरू होने से पहले सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करना चाहता है।

54. ***इसलिए,अत: सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में, अभियोजन पक्ष उन सभी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है जिन पर मुकदमा शुरू होने से पहले आरोपी को भरोसा दिया जा सकता है। इस प्रकार, दांडिक मुकदमों में अदालतों द्वारा बाद के चरण में साक्ष्य दाखिल करने की अनुमति देने की शक्ति के प्रयोग से अभियुक्त के प्रति गंभीर या अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए।***दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 या 311 या साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत अभियोजन पक्ष के किसी भी आवेदन की जांच करते समय, अदालत को पार्टियों के अधिकारों के संबंध में एक संतुलन कायम करना होगा। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, और न्यायालय यह देखने के बाद कि अभियुक्त निष्पक्ष सुनवाई की इच्छा से पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं है, विवेक का प्रयोग करता है न्यायालय उपयुक्त मामलों में अभियोजन पक्ष को बाद के समय में ऐसा प्रमाणपत्र पेश करने की अनुमति दे सकता है।***यदि अभियुक्त जो अपने बचाव के हिस्से के रूप में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो यह फिर से विधि के अनुसार न्यायालय द्वारा मामले में उपयोग किए जाने वाले विवेक पर निर्भर करेगा।***

72. संदर्भ का उत्तर इस प्रकार दिया गया है कि:

(क) जैसा कि हमने यहां ऊपर स्पष्ट किया है, अनवर पी.वी. (सुप्रा.), साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ख के आधार पर इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून है। टोमासो ब्रूनो (सुप्रा.) में निर्णय, प्रति इन्क्यूरियम होने के कारण, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है। इसके अलावा,शफी मोहम्मद (सुप्रा.) के रूप में रिपोर्ट की गई और 2011 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9431 में निर्णय और (2018) 5 एससीसी 311MANU/SC/0331/2018 के रूप में रिपोर्ट किया गया दिनांक 03.04.2018 का निर्णय: (2018) 5 एससीसी 311, सही रूप में विधि का निर्धारण नहीं करता है और इसलिए खारिज किया जाता है।

(ख) ऊपर उल्लिखित स्पष्टीकरण यह है कि यदि मूल दस्तावेज़ स्वयं प्रस्तुत किया गया है तो धारा 65ख(4) के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र अनावश्यक है। यह लैपटॉप

कंप्यूटर, कंप्यूटर टैबलेट या यहां तक कि मोबाइल फोन के मालिक द्वारा गवाह बॉक्स में जाकर यह साबित करके किया जा सकता है कि संबंधित डिवाइस, जिस पर मूल जानकारी पहली बार संग्रहीत की गई है, उसका स्वामित्व उसके पास है और/या उसके द्वारा संचालित है। ऐसे मामलों में जहां "कंप्यूटर" किसी "कंप्यूटर सिस्टम" या "कंप्यूटर नेटवर्क" का हिस्सा होता है और ऐसे सिस्टम या नेटवर्क को भौतिक रूप से न्यायालय में लाना असंभव हो जाता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी प्रदान करने का एकमात्र धारा 65ख(4) के तहत अपेक्षित प्रमाणपत्र के साथ साधन धारा 65ख(1) के अनुसार, हो सकता है। *अनवर पी.वी. में अंतिम वाक्य (सुप्रा.) जो इस प्रकार है "...यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है..." इस प्रकार स्पष्ट किया गया है; इसे "साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत..." शब्दों के बिना पढ़ा जाना चाहिए, इस स्पष्टीकरण के साथ, अनवर पी.वी. (सुप्रा.) के अनुच्छेद 24 में वर्णित विधि को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है।*

(ग) उन अदालतों द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से निपटते हैं, इसके बाद पैराग्राफ 62 (सुप्रा.) में जारी किए गए सामान्य निर्देशों का पालन करना होगा ताकि उनके संरक्षण को और उचित स्तर पर प्रमाणपत्रको प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। ये निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ग के तहत नियम और निर्देश बनाए जाने और दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन के लिए डेटा प्रतिधारण शर्तें तैयार किए जाने तक सभी कार्यवाहियों में लागू होंगे।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहतधारा 67 ग जैसी शक्तियों का प्रयोग करके, उचित नियम और निर्देश तैयार किए जाने चाहिए, और अपराधों के विचारण, उनके पृथक्करण,विचारण और अपील की पूरी अवधि के लिएअभिरक्षाश्रृंखला के नियमों, मुद्रांकन और रिकॉर्ड रखरखावमें शामिल डेटा के प्रतिधारण और भ्रष्टाचार से बचने के लिए मेटा डेटा के संबंध में उपयुक्त नियम भी तैयार किए जाने चाहिए। इसी तरह, अप्रैल, 2016 में मुख्य न्यायाधीश के सम्मेलन द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बादपूर्व में बनाए अनुसारइलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संरक्षण, पुनर्प्राप्ति और तैयार करने के लिए उचित नियम तैयार किए जाने चाहिए।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान मामले में, विचाराधीन साक्ष्य एक प्रासंगिक साक्ष्य है, जिसे शुरुआत में ही (गवाहों की मुख्य जांच के बाद) रिकॉर्ड पर लाने की मांग की गई थी, और अंतिम सुनवाई के समय इसकी स्वीकार्यता पर निर्णय लिया जा सकता है।

4.1 विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि सभी प्रासंगिक साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लाने का प्रयास होना चाहिए, और किसी भी त्रुटि के मामले में, उसे बाद में परीक्षण के दौरान ठीक किया जा सकता है, जैसा कि उपरोक्त उद्धृत मामले में निर्धारित किया गया है।

4.2 विद्वान अधिवक्ता ने ***श्याम सुंदर प्रसाद बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 588/2022)***के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा 6.6.2022 को दिए गए निर्णयतथा ***राहुल वर्मा बनाम सरकार (आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1269/2019)***में 23.09.2019 को दिए गए निर्णय पर भी भरोसा करते हुए ऐसी दलीलों को मजबूत किया।

7. विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया लेकिन वह याचिकाकर्ता की ओर से की गई दलीलों का खंडन करने में असमर्थ है।

8. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और न्यायालयिक द्वारा उद्धृत निर्णयों के साथ-साथ मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

9. निम्नलिखित निर्णयों को देखते हुए, इस न्यायालय ने पाया है कि विचाराधीन मुद्दे पर किसी भी निर्णय की आवश्यकता नहीं है; **राज कौर बनाम गुरजीत सिंह और अन्य (खंडपीठ आपराधिक अपील संख्या 151/2019)**में 26.07.2021 को इस माननीय न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा लिए गए निर्णय, जो इस माननीय न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा **दुर्गा कंवर राठौड़ बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एकलपीठ आपराधिक विविध (या.) 6516/2022)**में दिया गया 11.10.2022 का निर्णय, इस न्यायालय द्वारा सिद्धांत सिंह चरण बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 7206/2022) में दिनांक 06.12.2022 को दिया गया निर्णय।

उपर्युक्त निर्णयों के प्रासंगिक अंश यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:-

राज कौर (सुप्रा.) में:-

"आरोपी व्यक्तियों द्वारा आईओ (पीडब्लू-34) लक्ष्मण सिंह को कथित तौर पर दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप कोई आपत्तिजनक भौतिक तथ्य बरामद नहीं हुआ। इस प्रकार, सबूतों का एकमात्र नमूना जो रिकॉर्ड पर रहता है ताकि आरोपी को अपराध से जोड़ा जा सके, वह कॉल विवरण रिकॉर्ड के रूप में होगा। यह कहना पर्याप्त है कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड एकत्र करने वाले अतिरिक्त एस.पी. देवेन्द्र कुमार बिश्नोई (पीडब्लू 31) के साक्ष्यों को देखने पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने आरोपी और मृतक के बीच हुई कॉलों का विश्लेषण नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया और पाया कि आखिरी कॉल जो बूटा सिंह ने की थी वह 16.06.2013 की थी यानी घटना से लगभग 10-12 दिन पहले। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यानी कॉल डिटेल को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख के तहत सेवा प्रदाता द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रस्तुति अनिवार्य है। हालाँकि, गवाह श्री देवेन्द्र सिंह बिश्नोई ने अपनी प्रति जिरह में स्वीकार किया कि जो प्रमाणपत्र उसने प्राप्त किया था (प्रदर्श/45) वह केवल मृतक के कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से संबंधित था। कॉल विवरण को साबित करने के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं के किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई। इस प्रकार, कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी अभियोजन के लिए उपयोगी नहीं हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में कानून अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल एआईआर 2020 एससी 4908 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अच्छी तरह से तय हो गया है।

दुर्गा कंवर राठौड़ (सुप्रा):-

"4. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, 1872 के अधिनियम की धारा 65ख के तहत प्रमाणपत्र जारी करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना का निपटारा केवल ट्रायल कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है, जाहिर है, संबंधित पक्ष द्वारा दायर किसी अपील के अनुसरण में यह आश्वासन देने के बाद भी कि जांच अधिकारी या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद, 1872 के अधिनियम की धारा 65 ख के तहत प्रमाणपत्र प्रस्तुत या उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

5. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में सक्षम नहीं है कि सभी प्रयासों के बावजूद, राज्य मोबाइल कंपनी से अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।

6. जैसा भी हो.

7. यदि याचिकाकर्ता 1872 के अधिनियम की धारा 65 ख के तहत प्रमाणपत्रप्रस्तुत की आवश्यकता से छूट के लिए आवेदन दायर करता है, तो ट्रायल कोर्ट अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल और अन्य (2020) 7 एससीसी 1 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उचित सम्मान देते हुए कानून के अनुसार निर्णय लेगा।

सिद्धार्थ सिंह चारण (सुप्रा) में :-

"10. इस न्यायालय का मानना है कि दिनांक 30.09.2022 के आक्षेपित आदेश में 1872 के अधिनियम की धारा 65ख के तहत प्रमाणपत्र को खारिज करते हुए कहा गया है कि प्रमाणपत्र में आवश्यक विवरण शामिल थे यथा,याचिकाकर्ता का मोबाइल फोन नंबर और न ही किस मोबाइल फोन नंबर से विचाराधीन संदेश प्राप्त हुए थे, आदि, जैसा कि उपरोक्त धारा में निहित कानून के प्रावधान द्वारा अधिदेशित है।

11. यह न्यायालय यह भी मानता है कि 1872 के अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाणपत्र जमा करने के संबंध में कानून को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सोनू @ अमर (सुप्रा.) के मामले में तय किया है, जिसे दोहराया गया और आगे अर्जुन पंडितराव खोतकर (सुप्रा.) के मामले में स्पष्ट किया गया।

संक्षिप्तता के लिए, उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग यहां नीचे दिया गया है:

"हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि धारा 65ख उस चरण के बारे में बात नहीं करती है जब ऐसा प्रमाणपत्र न्यायालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनवर पी.वी. (सुप्रा.),मामले में इस न्यायालय ने यह देखा कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर इस तरह के प्रमाणपत्र को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हम केवल यह कह सकते हैं कि ऐसा उन मामलों में होता है जहां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर भरोसा करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां या तो दोषपूर्ण प्रमाणपत्र दिया गया है, या ऐसे मामलों में जहां ऐसे प्रमाणपत्र की मांग की गई है और संबंधित व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया है, मुकदमे पर विचारण करने वाले न्यायाधीश को साक्ष्य अधिनियमकी धारा 65ख(4) में निर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों को बुलाना होगा और यह आवश्यक है कि ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे

व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा दिया जाए। ट्रायल जज को ऐसा तब करना चाहिए जब उपरोक्त परिस्थितियों में आवश्यक प्रमाणपत्र के बिना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में उसके सामने पेश किया जाता है। निःसंदेह, यह सिविल मामलों में कानून के अनुसार और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर न्याय की आवश्यकताओं के अनुसार विवेक के प्रयोग के अधीन है। जब दांडिक विचारण की बात आती है, तो इस सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखना जरूरी है कि अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत विचारण शुरू होने से पहले ऐसे सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करना चाहता है।

...

इसलिए, सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में, अभियोजन पक्ष उन सभी दस्तावेजों को आरोपी व्यक्ति को विचारण शुरू होने से पहले प्रदान करने के लिए बाध्य है जिन पर भरोसा किया जा सकता है। इस प्रकार, दांडिक मामलों में विचारण अदालतों द्वारा बाद के चरण में साक्ष्य दाखिल करने की अनुमति देने की शक्ति के प्रयोग से अभियुक्त के प्रति गंभीर या अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 या 311 या साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत अभियोजन पक्ष के किसी भी आवेदन की जांच करते समय, अदालत को पार्टियों के अधिकारों के संबंध में संतुलित रूख अपनाना होगा। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, और न्यायालय यह देखने के बाद विवेक का प्रयोग करता है कि अभियुक्त निष्पक्ष सुनवाई की इच्छा से पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं है, न्यायालय उपयुक्त मामलों में अभियोजन पक्ष को बाद के समय में ऐसा प्रमाणपत्र पेश करने की अनुमति दे सकता है। यदि अभियुक्त अपने बचाव के हिस्से के रूप में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो यह फिर से कानून के अनुसार मामले में न्यायालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले विवेक पर निर्भर करेगा।

12. इस प्रकार न्यायालय का मानना है कि निम्न विद्वान न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश के माध्यम से, सही माना है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राथमिकता किया गया प्रश्नगत प्रमाणपत्र, कानून के अनुपालन में प्रस्तुत नहीं किया गया था। हालाँकि, यहाँ ऊपर उल्लिखित निर्णयों के मद्देनजर, ऐसे दोषपूर्ण प्रमाणपत्र को मामले की योग्यता के आधार पर, संबंधित न्यायालय के कहने पर ठीक किया जा सकता है।

13. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय

ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर लाने के लिए मांगे गए दस्तावेज़ उसके बचाव के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और इस प्रकार, 1872 के अधिनियम की धारा 65ख के अनुसार आवश्यकताओं का उचित अनुपालन करने के बाद, याचिकाकर्ता को इसे दाखिल करने का अवसर दिया जाना न्याय के हित में होगा।

14. "इसलिए वर्तमान याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है; निचली अदालत द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.09.2022 को रद्द कर दिया गया है और रद्द कर दिया गया है; नीचे दिए गए विद्वान निचली अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन को बहाल किया जाता है। जबकि उक्त धारा में निहित विधि के प्रावधानों का उचित अनुपालन करते हुए याचिकाकर्ता को 1872 के अधिनियम की धारा 65 ख के तहत प्रमाणपत्र दाखिल करने की स्वतंत्रता देते हुए वर्तमान सीमित हस्तक्षेप किया गया है, और याचिकाकर्ता को विद्वान न्यायालय के समक्ष अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएंगे; यह भी निर्देशित किया जाता है कि निचली अदालत इस पर नए सिरे से सख्ती से कानून के अनुसार विचार करेगी। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया है।"

10. हालाँकि, यह न्यायालय निम्नलिखित टिप्पणियाँ करना उचित समझता है;

10.1 इस न्यायालय का मानना है कि दांडिक न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों की आवश्यकता है कि किसी अभियुक्त को कानून के अनुसार सख्ती से अपना बचाव प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। प्रयास यह होना चाहिए कि सभी प्रासंगिक साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लिया जाए और यह सीमा तब अधिक होती है जब किसी दांडिक मुकदमे में कोई आरोपी अपने बचाव में साक्ष्य, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो या अन्यथा, रिकॉर्ड पर लाना चाहता हो।

10.2 अर्जुन पंडितराव खोतकर (सुप्रा.) के मामले में स्पष्ट की गई कानूनी स्थिति के लिए आवश्यक है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाया जाए, यदि द्वितीयक साक्ष्य है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख(4) के अनुसार एक प्रमाणपत्र के साथ होना चाहिए और इसमें किसी भी दोष के मामले में, संबंधित पक्ष को इसके लिए अपेक्षित अवसर प्रदान करने के बाद, संबंधित पक्ष द्वारा बाद के चरण में इसको ठीक किया जा सकता है। संबंधित न्यायालय को ऐसे उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे व्यक्ति(यों) को समन जारी करना चाहिए। इसके बाद, इसे कानून के अनुसार,

संबंधित न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज किया जा सकता है।

10.3 हालाँकि, मूल को उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को स्वयं लाकर जिस पर मूल जानकारी सबसे पहले संग्रहीत की गई है, या ऐसे उपकरण के मालिक के माध्यम से गवाह बॉक्स में कदम रखकर और यह साबित करके कि संबंधित उपकरण, जिस पर मूल जानकारी सबसे पहले संग्रहीत की जाती है, उसके स्वामित्व में है और/या उसके द्वारा संचालित है, सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में,ऐसे साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य बन जाते हैं, और धारा 65ख(4) के तहत प्रमाणपत्र की आवश्यकता तदनुसार समाप्त हो जाती है।

11. वर्तमान मामले में, विचाराधीन साक्ष्य घटना के सीसीटीवी फुटेज से संबंधित है, जो निर्विवाद रूप से एक प्रासंगिक साक्ष्य है।

12. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, और दिए गए तथ्यात्मक मैट्रिक्स के साथ-साथ उपरोक्त निर्णयों को देखते हुए, वर्तमान याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। निचली अदालत द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.09.2022 में केवल इस हद तक हस्तक्षेप किया जाता है कि निचली विद्वान अदालत संबंधित पुलिस प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को आरोप पत्र के साथ दी गई प्रतिलिपि सीडी रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति देगी। ऐसा विचार निम्न विद्वान न्यायालय द्वारा, सख्ती से कानून के अनुसार, और अर्जुन पंडितराव खोतकर (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी), न्यायमूर्ति

35-SKant/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।